ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-8* October- 2020
Innovation The Research Concept

कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Corona Virus Impact on Indian Economy

Paper Submission: 15/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

विमल कान्त
असिस्टेंट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढौरा,
हरिद्वार,
उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

आर्थिक संदर्भो से बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से पहले भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। हालांकि वर्ष 2019 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी तथापि वित्त वर्ष 2019–2020 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.7 प्रतिशत थी जो गत 6 वर्षो में विकास दर का सबसे निम्नतम स्तर था। 45 वर्षों में वित्त वर्ष 2019–2020 में भारत में बेरोजगारी की दर सबसे उच्चतम स्तर पर थी। वर्ष 2019 के अंत में देश के 8 प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन 5.2 प्रतिशत तक गिर गया। यह गत 14 वर्षों में सबसे खराब स्थिति थी। बुद्धिजीवियों के अनुसार कोविड–19 ने लोगों के स्वास्थ्य को तो प्रभावित किया है वहीं आर्थिक क्षेत्र में इसने 'कोढ़ में खाज' का काम किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे असंगठित क्षेत्र अपना विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह क्षेत्र देश के करीब 94 प्रतिशत आबादी को रोजगार देता है। लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है भारत में लॉकडाउन को अचानक लागू कर दिया गया जिससे करोड़ो लोगों रोजगार छिन गया और उनकी अजीविका पर भयंकर संकट उत्पत्र हो गया। सरकार ने लोगों मदद करने के लिये राहत पैकेजों की घोषणा की। यह घोषणा गरीबों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से हुई। राहत पैकेज की घोषणा से भारत के करीब 80 करोड़ लोगों को राहत मिलने का अनुमान है। खातों में पैसे डाल कर खाद सुरक्षा का बंदोबस्त करके सरकार गरीबों दैनिक मजदूरी करने वालों किसानों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की मदद कर रही है। 50 हजार करोड़ लागत की गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई गई इस योजना में प्रवासी मजदूरों को 25 तरह के काम के विकल्प उपलब्ध कराये जायेंगें। मिशन मोड़ में इस योजना में 125 दिनों तक काम चलेंगा। बुद्धिजीवी सरकार के इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं लेकिन उनका यह भी मानना हैं कि अर्थव्यवस्था को इस संकट के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए यह मदद पर्याप्त नहीं है सरकार को और अधिक आर्थिक मदद करने की आवश्यकता है।

Talking about economic references, the Indian economy was not in a very good condition even before the Corona crisis. Although India's economy was the fastest growing economy in the world before 2019, the growth rate of India's economy was 4.7 percent in FY 2019-2020 which was the lowest level of growth in the last 6 years. The unemployment rate in India was the highest level in 45 years in FY 2019-2020. At the end of 2019, production in the industrial sector fell by 5.2 percent in 8 major regions of the country. This was the worst situation in the last 14 years. According to intellectuals, Kovid-19 has affected the health of the people, while in the economic field, it has done the work of 'leprosy in leprosy'. The unorganized sector holds special significance in the Indian economy as it employs about 94 percent of the country's population. The unorganized sector has been the most affected by the lockdown. The lockdown was suddenly implemented in India, causing loss of millions of jobs and causing a severe crisis on their livelihood. The government announced relief packages to help the people. The announcement was aimed at reducing the economic burden on the poor. The announcement of relief package is expected to provide relief to about 80 crore people in India. The government is helping the poor daily wage laborers and those deprived of basic facilities by putting money in accounts and arranging fertilizer security. Poor welfare employment scheme costing 50 thousand crores was launched, in this scheme, 25 types of work options will be provided to the migrant laborers. In the mission diversion, this scheme will work for 125 days. The intellectuals are appreciating these efforts of the government but they also believe that this help is not enough to save the economy from the bad effects of this crisis, the government needs more financial help.

मुख्य शब्द : भारतीय अर्थव्यवस्था, कोरोना वायरस, बेरोजगारी, विकास दर, अजीविका ।
Indian Economy, Corona Virus, Unemployment, Growth Rate, Ajivika

प्रस्तावना

चीन के प्रान्त हुबेई की राजधानी वुहान से फैले कोरोना वायरस (Covid-19) ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। भारत में भी 70 दिनों (22 मार्च–31मई 2020) का लॉकडाउन घोषित किया गया। इस कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में अत्यधिक जनहानि की हैं, वहीं पर इसने अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। सारे उद्योग–धन्धे बंद हो गये, कंपनियाँ बंद, हवाई यात्राएं, रेल यात्राएं बस यात्राएं रद्द कर दी गयी हैं, जिसका खामियाजा भारत ही नही पूरी दुनिया भुगत रही है।

भारत सरकार के अनुसार लॉकडाउन से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने में तो मदद मिली है, परन्तु लॉकडाउन के कारण लोगों और अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुँची है। वित्त मंत्रालय का एक अनुमान है कि लॉकडाउन के प्रथम 21 दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था को 8.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। लॉकडाउन के कारण जो वित्तीय हानि हुई है उसकी पूर्ति वर्ष 2020–21 में कर पाना असंभव हो सकता है। लॉकडाउन से ऑटोमोबाइल, उद्योग, पर्यटन उद्योग, शेयर बाजार और दवा कंपनियों सहित कई सेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं। देश–दुनिया के बड़े–बड़े समारोह भी टाल दिए गए हैं। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत के व्यापार पर भी पड़ा है। लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था को करीब 34.8 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध–पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोधपत्र के लिए समाचार पत्रों का प्रयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार टीवी और इंटरनेट का भी सहारा लिया गया है।

शोध का उद्देश्य

भारत में कोरोना का सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना।

कोरोना महामारी (कोविड–19) का बुरा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में भारत पर देखने को मिल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के लगभग 75 प्रतिशत भाग ने पूर्णबंदी की मार को झेला है। अगर स्थिति ज्यादा खराब होती है तब कोविड–19 महामारी देश के लिए पूरी तरह से नकदी का संकट बन जाएगी और कंपनियों के कारोबार पर भी संकट दिखेगा और बैंक अपनी बैलेंस शीट में गिरावट से जूझेंगे। **नोमुरा का** कहना है कि इसके बेरोजगारी बढ़ने, आमदनी में नुकसान और सख्त उपायों के खिलाफ निराशा बढ़ने से सामाजिक अशांति भी पैदा हो सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर का क्षेत्रवार विवरण

मजदूरों पर प्रभाव

भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए लोग खेती का काम पूरा करने के बाद बुआई से कटाई के बीच के समय का सदुपयोग करने के लिए रोजी–रोटी के चक्कर में शहरों को पलायन कर जाते हैं। चूँकि कोरोनावायरस के खतरों को रोकने के लिए सरकार को अचानक लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा जिससे घर से दूर काम करने वाले मजदूर घबरा गए। चूंकि खेती की कटाई का समय था इसलिए मजदूर इस लॉकडाउन को तोड़ते हुए अपने घर को पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करने का फैसला लिया। चूँकि लॉकडाउन की वजह से नौकरियां छिन गई थी और खाने–पीने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। अधिकांशतः मजदूर झुग्गी–झोपड़ियों में या फुटपाथ पर रहते हैं तथा वे अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाकर रखते सारी कमाई घर भेज देते हैं। दूसरा कारण यह भी था कि एक तरफ सरकार का यह अचानक फैसला था तो दूसरी तरफ खेती की कटाई का भी समय था। हालांकि सरकार ने खाने–पीने की समुचित व्यवस्था के लिए आश्वासन दिया था और यह भी घोषणा की थी कि पंजीकृत मजदूरों के खाते में प्रति माह एक–एक हजार रुपए दिए जाएंगे, परंतु ये मजदूर न तो पंजीकृत थे और न ही राशन कार्ड धारक थे।

नीति आयोग की नवंबर 2018 में आई 'स्ट्रैटिजी फॉर न्यू इंडिया/75' रिपोर्ट में बताया गया है कि *"देश के इनफॉर्मल सेक्टर में कुल* श्रमिको *में से करीब 85 प्रतिशत को रोजगार मिला हुआ है।"* इससे पता चलता है कि रोजगार के मामले में इस क्षेत्र की कितनी बड़ी भूमिका है। ये मजदूर भारत की राष्ट्रीय–आय में 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इसलिए उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा माना जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइजीरिया और ब्राजील में लॉकडाउन और अन्य नियंत्रण उपायों से बड़ी संख्या में औपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिक प्रभावित हुए हैं इसके मुताबिक भारत में किया गया लॉकडाउन से श्रमिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, और उन्हें अपने गांव की ओर लौटने को मजबूर होना पड़ा है। भारत में करीब 90 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कोरोना के इस संकट से लगभग 40 करोड़ लोग बेरोजगारी में फंस सकते हैं और इस वर्ष दुनिया में 19.5 करोड़ पूर्णकालिक रोजगार छूट सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑन इंडियन इकोनामी के अनुसार इस लॉकडाउन में 23.4 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। जनवरी से मार्च के बीच रोजगारों की संख्या 41 करोड़ 10 लाख से घटकर 39 करोड़ 60 लाख हो गयी है और बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 80 लाख हो गई है।

रोजगार के मोर्चे पर करीब 52 फीसदी कंपनियों को कोविड–19 के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण अपने

संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान की आशंका दिख रही है। सी0आई0आई0 ने कहा कि जिस अनुपात में छंटनी की आशंका जताई जा रही है वह काफी चौंकाने वाली है। करीब 47 फीसदी कंपनियों ने कहा कि करीब 15 फीसदी छंटनी होने के आसार हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि 32 फीसदी कंपनियों ने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 15 से 30 फीसदी के दायरे में छंटनी हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के श्रम–निकाय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 400 करोड़ लोग गरीबी के जाल में फंस सकते हैं। एक अनुमान है कि वर्ष 2020 में दुनिया भर में लगभग 19.5 करोड़ लोगों की अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई0एल0ओ0 ने अपनी रिपोर्ट आई0एल0ओ0 निगरानी दूसरा संस्करण में कोरोना वायरस संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है।

आई0एम0ओ0 के महानिदेशक गाय राइडर ने मंगलवार को कहा विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों और व्यवसायियों को तबाह करने का सामना करना पड़ रहा है हमें तेजी से निर्णायक रूप से एक साथ कदम उठाने होंगे रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 2 अरब लोग औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं इनमें से ज्यादातर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था में हैं और यह विशेष रूप से संकट में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट से पहले ही अनौपचारिक क्षेत्र के लाखों श्रमिक को प्रभावित हो चुके हैं।

राइडर ने कहा है कि करोना काल पिछले 75 वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सबसे कठिन परीक्षा है, यदि इस परीक्षा कोई एक विफल होता है तो हम सभी विफल हो जाएंगे। हमें समाज के सभी वर्गों की मदद करनी चाहिये, विशेष रूप से उनकी जो सबसे कमजोर है। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार में सबसे अधिक गिरावट अरब देशों में को जिसके बाद यूरोप और एशिया प्रशांत में देखने को मिलेगी।

मूडीज का अनुमान है कि करोना वायरस के प्रभाव और लॉकडाउन की वजह से भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2020 में 40 प्रतिशत तक घट सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2021 में यह 8.7 प्रतिशत और उसके बाद के सालों में 6 प्रतिशत के करीब रह सकती है यह विकट संकट की घड़ी है 130 करोड़ आबादी वाले देश में 70 दिनों के लिए पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया और कारोबार पूरी तरह ठप है बड़ी और उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिली।

आप्रवासी मजदूर

प्रोफेसर अरुण कुमार का मानना है वह कहते हैं कि लॉकडाउन के वक्त जब अतिरिक्त मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है। गरीब लोग उस तक कैसे पहुंचेंगे। इन घोषणाओं को जमीनी स्तर को करना सबसे बड़ी चुनौती है सरकार को सेना और राज्यों की मशीनरी की मदद से सीधे गरीबों तक खाने की चीजें पहुंचानी चाहिए।

भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष के अनुसार इस समय सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए। आरबीआई से उधार लेकर लोगों पर खर्च करना चाहिये।

आयात पर प्रभाव

हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीन और दुनिया के अन्य देशों में COVID-19 के प्रकोप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार, सप्लाई चैन का व्यवधान, वस्तुओं और लोजिस्टिक्स सहित अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

आयात में चीन पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है, प्रथम 20 उत्पादों में से (एचएस कोड के दो अंकों में) जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन उनमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक आयात में चीन लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा रखता है। भारत मशीनरी और जूव–पिजी कार्बनिक रसायन का सामान में 33 प्रतिशत चीन से खरीदता हैं। उर्वरकों और मोटर वाहन कलपुर्जों के लिए भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक है। लगभग 65 से 70 प्रतिशत सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री और लगभग 90 प्रतिशत मोबाइल फोन चीन से भारत में आते हैं। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीन पर आयात निर्भरता का भारत के औधोगिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

पर्यटन कारोबार पर प्रभाव

कोरोना का पर्यटन कारोबार पर भी असर दिखने लगा है क्योंकि सभी देशों ने चीन और कोरोना वायरस से प्रभावित दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने आगामी महीनों के लिए अपनी यात्रा रद्द करनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को जो भी वीजा और ई–वीजा 3 मार्च 2020 या उससे पहले जारी किए गए हैं और जिन्होंने अभी भारत में प्रवेश नहीं किया है, वो सभी वीजा तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के मुताबिक विमानन उद्योग को यात्रियों से होने वाले कारोबार में कम से कम 63 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस अनुमान में माल ढुलाई के व्यापार को होने वाला नुकसान शामिल नहीं है।

कृषि क्षेत्र पर प्रभाव

सरकार ने किसानों की मदद करने के लिये राहत पैकेज घोषणा की। सरकार ने किसान सम्मान नीधि के अर्न्तगत अप्रैल से तीन महीने तक किसानों के खातों में हर महीने 2000 रुपये डाले। सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये पहले ही देती थी। इसलिये यह कदम पर्याप्त नहीं है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि दो हजार रुपये की मदद पर्याप्त नहीं है क्योंकि निर्यात ठप हो चुका है, शहरी क्षेत्रों में कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि मांग बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कीमतें गिरेंगी क्योंकि किसान अपनी फसल बेच नहीं पाएंगे।

यह संकट बेहद गंभीर समय में आया है, जब नई फसल तैयार है और बाजार भेजे जाने के इंतजार में

है। भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कठिन लॉकडाउन की स्थिति में गांवों से खाने–पीने की ये चीजें शहरों और दुनिया के किसी भी देश तक कैसे पहुंचेंगी? अगर सप्लाई शुरू नहीं हुई तो खाना बर्बाद हो जाएगा और भारतीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत की कुल आबादी का 58 फीसदी हिस्सा खेती पर निर्भर है और देश की अर्थव्यस्था में 256 बिलियन (लगभग 17प्रतिशत) डॉलर का योगदान है।

कारोना की वजह से कृषि सहायक उद्योगों जैसे पशु पालन, मुर्गी पालन आदि में लगे लोगों का भी बुरा हाल है। पोल्ट्री फार्म तो बर्बादी की कगार पर पहुंच गये हैं। प्रायः नवरात्रि के बाद मुर्गों की मांग बढ़ती है, इस कारण पोल्ट्री फार्म वाले एक महीने पहले से बड़ी लाट की तैयारी करते हैं, चूजों पर सभी प्रकार के खर्च करने के बाद उत्पादन और बिक्री के स्तर तक पहुंचने से पहले ही लॉक डाउन हो जाने से मीट के लिये मुर्गे का बाजार चौपट हो गया और पोल्ट्री वालों की बड़ी पूँजी फंस गयी। इसी प्रकार पशु–पालकों की भी स्थिति चिंता जनक है। मिठाई की दुकानों, होटल आदि में होने वाली दूध, खोया, पनीर, छेना आदि की खपत लगभग शून्य हो गयी। इस प्रकार दूध की खपत घट कर 40 प्रतिशत पर आ गयी। प्रति वर्ष गर्मी में दूध का खुला बाजार 50 रूपये लीटर हुआ करता था जो इस समय 15 रूपये पर आ गया है, जिससे लागत भी नही निकल पा रही है। उधर भूसे की आपूर्ति न होने के कारण इसका दर 1500 रूपये प्रति कुंतल तक चला गया है, चूनी, चोकर, खली जैसी वस्तुओं की भी बाजार में आपूर्ति कम हो जाने से मूल्य बढ़ा है जिसका असर पशु–पालकों पर पड़ा है।

बताया है कि उनके पास अभी मार्च तक का स्टॉक है। अगर आने वाले समय में चीन से सामान की सप्लाई नहीं शुरू

ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (SIAM) का कहना है कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में करीब 3.7 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसका अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 30 प्रतिशत है। भारत में ऑटो उद्योग पहले से ही आर्थिक सुस्ती का शिकार था। अब चीन में मंदी के कारण भारत के ऑटो उद्योग को भी कल–पुर्जों की किल्लत हो रही है। ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक विनी मेहता कहते हैं, हम अभी तो घबराहट के शिकार नहीं हैं लेकिन चिंतित जरूर है। बाजार के बड़े खिलाड़ियों ने हमें होगी तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं। तब हमें स्थानीय स्तर पर अपने लिए नए विकल्प तलाश करने होंगे। ऑटो उद्योग की कई बड़ी कंपनियों ने कहा है कि उन्हें कल–पुर्जों की आपूर्ति में परेशानी उठानी पड़ रही है। टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के प्रभावों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।

शेयर बाजार पर प्रभाव

कोरोना वायरस की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के शेयर बाजारों की हालत बहुत खराब है। हालत इतनी खराब हो गये हैं कि 13 मार्च 2020 को सेंसेक्स और निफ्टी 10 फीसदी से अधिक लुढ़क गए थे और इस वजह से ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। यानी कुछ देर तक शेयर बाजार में कारोबार नहीं हुआ। निवेशक ने ना तो शेयर खरीद सके और ना ही बेच सके। ये ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए रोकी गई। मालूम हो कि जब बाजार में 10 फीसदी या उससे अधिक की गिरावट आती है, तो उसमें लोअर सर्किट लग जाता है और ट्रेडिंग कुछ देर के लिए रोक दी जाती है। बाजार में सर्किट के इतिहास पर नजर डाले तो बाजार में 12 साल में पहली बार लोअर सर्किट लगा है और 25 सालों में पहली बार इतनी गिरावट देखी गयी है।

भारतीय शेयर बाजार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 13 मार्च को शुरुआती कारोबार में 15 मिनट से भी कम समय में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए थे। गुरुवार को भी बाजार ऐतिहासिक गिरावट के साथ बंद हुआ था। तब शेयर बाजार के पतन के चलते निवेशकों के 11.42 लाख करोड़ रुपये डूब गए थे। इतना ही नहीं, सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 9 मार्च को भी सेंसेक्स–निफ्टी में एक दिन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तब बीएसई में निवेशकों की संपत्ति 6.84 लाख करोड़ रुपये कम हो गई थी।

कोरोना का सामाजिक प्रभाव

विश्लेषक मानते हैं कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने के साथ ही राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा है। लगभग हर देश के लोग, किसी न किसी समुदाय से खतरा महसूस करते हैं या अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझते हैं। बीते कुछ समय के भारत को देखें तो यहां सांप्रदायिक समीकरणों की वजह से लगातार सामाजिक समीकरणों को बिगड़ते देखा जाता रहा है। अब जब दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप फैल गया है तो इससे सामाजिक दूरियों का बढ़ना तय है। उदाहरण के लिए ले लिया जाय तो चीन के साथ दुर्व्यवहार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि चीन से ही यह महामारी फैली है। अभी समाज, देश और दुनिया बंटे हुये तो हैं लेकिन यह बिलकुल अलग तरह और वजह से हुआ है। इस समय अपने परिवार को छोड़कर लोग पड़ोसी से भी बात नहीं कर रहे हैं तो यह मजबूरी की वजह से है। यही बात देशों के एक–दूसरे से कटने के बारे में भी कही जा सकती है, जो कि कोरोना का ही असर है।

सरकार को कुछ सुझाव

यह बात हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से गुजर रहा है जिसके चलते भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए कई उपाय किये हैं, फिर भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं। जो इस तरह हैं–

1. एक तरीका तो ये है कि सरकार और आर्थिक राहत लेकर आये जो वित्तीय प्रतिबद्धता और प्रसार में पिछले पैकेजों से अधिक हो।
2. इसके लिए आवश्यक धन जुटाने और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए कुछ आउट–ऑफ–द–बॉक्स विचारों की जरूरत है।
3. सरकार को अभी के लिए वित्तीय रुढ़िवादिता के बारे में भूल जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था के लिए जो भी पैसे खर्च करने की जरूरत है उससे किया जाना चाहिए जैसा कि विकसित देशों के द्वारा किया जा रहा है।
4. 26 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा घोषित 1.7 लाख करोड़ का पैकेज एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन ये जीडीपी का सिर्फ 1 प्रतिशत है– जबकि भारत को जीडीपी का कम से कम 5 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। (करीबन 10 लाख करोड़)
5. गरीबों को नकद हस्तांतरण में अगले 3 महीनों के लिए कम से कम रु 3000 माह देना चाहिए।
6. फसल की कटाई के समय किसानों को अपनी उपज को मंडियों में से जाने के लिए लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान किया जाना चाहिए।
7. ऋणदाताओं को अपने सवंद ऋण खातों को पुनर्निर्धारित करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
8. कम से कम MSMEs के लिए Bankruptcy Code को अगले 6 महीनों के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।
9. अगले 6 महीनों के लिए GST Holiday करना चाहिए। इससे नुकसान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होगा, लेकिन वास्तविक नुकसान से यह कम होगा, क्योंकि व्यापर बिलकुल ठप्प है। इस वक्त यह व्यापार के लिए बैी सिवू की स्थिति को मजबूत करेगा और वैधानिक अनुपालन के बोझ को कम करेगा ताकि कारोबार जल्दी वापस ट्रैक पर आ सके।
10. केंद्र को लॉकडाउन के दौरान आजीविका को बचाने के लिए अपनी टेक्स से होने वाली आय में ढील राजस्व खर्चे में बढ़ोतरी करके करनी चाहिए।
11. उद्योग निकाय यह चाहते हैं कि सरकार बहुत ही सुलझी हुयी नीति अपनाये जिससे अर्थव्यवस्था फिर से शुरू करने में मदद मिले क्योंकि अगर आर्थिक गतिविधियां अब भी बंद रही तो नुक्सान की भरपाई नहीं हो पायेगी।

निष्कर्ष

लॉकडाउन की वजह से आर्थिक व्यवस्था तो चरमराई ही इसका सामाजिक प्रभाव भी नकारात्मक रूप से पड़ा है। लोग उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहते हैं, जिनमें कोरोना के मामूली लक्षण भी दिख जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। लोग घरों में रहकर परिवार के साथ खुश हैं, क्योंकि उनके पास कभी परिवार के लिए समय ही नही रहता था। इस प्रकार कोरोना वायरस का समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार सभी क्षेत्रों को देखें तो पता चलता है कि अर्थव्यवस्था चाहे भारत की हो या वैश्विक, सभी की स्थिति नाजुक है। इस समय सभी देश कोरोना से लड़ाई में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना से जीत गए तो अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी, पर हार गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सरकार ने 31 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन चरणो में हटाया जिससे कोरोना को रोका जा सकें। जब सरकार ने लॉकडाउन पर फैसला लिया था तो दो ही विकल्प थे–जीवन बचाना या आजीविका सुनिश्चित करना। सरकार ने तब जीवन बचाने को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब जैसे–जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ी अर्थव्यवस्था और आजीविका पर हुए गंभीर नुकसान स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। यह भी जाहिर बात है कि रोजगार नहीं होने के कारण लोग भूख से भी मरें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया भर के देश एक हत्यारे से लड़ने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *सत्याग्रह*
2. *द प्रिंट*
3. *अमर उजाला समाचार पत्र*
4. *योजना मासिक पत्रिका*
5. *कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका*
6. *http://thewirehindi.com/116663 /international-labor-organization-report-indiaworker-poor*
7. *https://economictimes.indiatimes.com/hindi/news/covid-19-lockdown-may-costthe-economy-rs-8-76-lakhcrore/articleshow/75021462.cms?from=mdr*
8. *https://www.amarujala.com/photo-gallery/business/business-diary/covid-19-coronavirus-is-affecting- indian-economy-anddifferent-sectors*
9. *https://hindi.businessstandard.com/storypage.php?autono=167839*
10. *http://thewirehindi.com/116663 /international-labor-organization-report-indiaworker-poor/*
11. *https://hindi.newsclick.in/40- crore-workers-in-India-may-be-trapped-in-povertyUN-report*
12. *www.bbc.com*
13. *www.ugtabharat.*
14. *http://thewirehindi.com/116663/international-labor-organization-report-india-worker-poor/*